

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 8
07 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को बढ़ावा देना

8. डा. सी. एम. रमेश:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में नई सहकारी समितियों को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): देश में नई सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए तथा जमीनी स्तर तक उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कई पहल किए हैं जिनमें, निम्न शामिल हैं:

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक जैसे, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, को सदस्य ऋणदाता संस्थान (मेम्बर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन) के रूप में शामिल किया है जो सहकारी क्षेत्र में ऋण उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- प्राथमिक कृषि साख समितियों के मॉडल उपनियम का (पैक्स) निर्माण किया गया है जो उन्हें डेयरी/डीजल/पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, मत्स्य पालन, सामान्य सेवा, बैंकिंग संवाददाता, वितरक केंद्र आदि, जैसी विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर बहुउद्देशीय सोसायटी बनने में सक्षम बनाता है।
- सहकारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन सी.एस.आई.एस.ए.सी. योजना के तहत सब्सिडी अनुदान / 2021 के रूप में वर्ष-341 में 22.47 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 67.करोड़ रुपये की 9 वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एन.सी.डी.सी., सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है जो सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक ,जिला सहकारी विपणन समितियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत करने/ प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापनाकोल्ड च ,भंडारण सुविधाओं ,ेन की स्थापना और आधुनिकीकरण"युवा सहकार" सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार के लिए , योजना , स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करनेकरने के लिए "आयुष्मान सहकार"योजना और महिला सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए "नंदनी सहकार" योजना, आदि का कार्यान्वयन करता है।

सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एन.सी.डी.सी. सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है और इसने संचयी रूप से देश में सहकारी समितियों के विकास के लिए 31.03.त 2022क 2,11,करोड़ 549 रुपये की राशि वितरित की है।

पिछले तीन वर्षों में एन.सी.डी.सी. ने सहकारी समितियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता वितरित की है:

वित्तीय वर्ष -2021-22 -34,221 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष -2020-21 -24,733 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष -2019-20 -27,703 करोड़ रुपये।

एन.सी.डी.सी. द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण अनुबंध-। के रूप में संलग्न है।

**पिछले 3 वर्षों में एनसीडीसी द्वारा राज्य/संघराज्य क्षेत्र के अनुसार निधि का संवितरण
(करोड़ रुपयेमें)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1	vaMeku fudkseckj }hi lewg	10.28	-	-
2	vka/kz izns'k	405.62	603.98	2,831.59
3	v:.kkpy izns'k	7.56	1.44	0.25
4	vle	14.34	5.59	3.57
5	fegkj	454.40	1,633.60	2,857.90
6	paMhx<+	-	-	0.03
7	NRrhlx<+	5,500.35	12,000.07	12,400.87
8	neu ,oanho	-	-	-
9	fnYyh	-	2.32	0.34
10	xksok	0.11	0.19	-
11	xqtjkr	118.34	52.25	37.40
12	gfj;k.kk	6,608.58	6,645.11	12,827.75
13	fgekpy izns'k	59.69	36.90	14.74
14	tEew ,oa d'ehj	-	-	0.13
15	>kj[kaM	8.25	0.92	1.79
16	dukZVd	151.67	170.69	164.49
17	dsjy	363.89	303.54	371.85
18	e/; izns'k	1,081.70	208.36	477.10
19	egkjk"V ^a	1,015.07	1,145.59	688.07
20	ef.kiqj	4.79	-	0.04
21	es?kky;	-	57.80	0.04
22	fetksje	-	2.16	1.06
23	ukxkySaM	13.37	6.07	0.17
24	vksfM'kk	3.75	0.80	4.06
25	iatkc	135.28	22.77	0.13
28	jktLFkku	7,256.74	157.80	7.79
29	flfDde	-	-	-
30	rfeyukM	21.24	21.58	50.75
31	rsyaxkuk	3,568.83	739.88	1,092.20
32	f=iqjk	3.05	3.20	3.00
33	mRrj izns'k	673.10	827.95	252.33
34	mRrjk[kaM	12.34	17.22	80.36
35	if'pe caxky	128.35	59.13	44.16
36	अन्य	82.74	6.29	7.12
	कुल योग	27,703.43	24,733.23	34,221.08